



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 133]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2019

(मामला सं: एसएसआर-01/2019)

विषय : पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

फा. संख्या 7/3/2019-डीजीटीआर.—मै. सेंट-गोबैन इंडिया प्रा. लि., मै. सिसकम फ्लैट ग्लास इंडिया लि. और मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि. (जिन्हें आगे आवेदक या याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

- और यतः याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

क. पृष्ठभूमि

3. यतः पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2013 की जाँच शुरूआत अधिसूचना सं 14/25/2012-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2014 की अपनी अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/25/2012-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2014 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाया गया था।

ख. संबद्ध देश

4. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में संबद्ध देश पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों शामिल) के रेंज की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास” हैं जिनकी मामूली मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (जिन्हें आगे ‘संबद्ध वस्तु’ भी कहा गया है)। चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच के समान ही रहेगा।
6. संबद्ध वस्तु को ‘शीशा और शीशे की वस्तुएं’ अध्याय शीर्ष 70 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है यद्यपि इसका वर्गीकरण और आयात विभिन्न उपशीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 आदि के अंतर्गत भी किया जा रहा है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घ. समान वस्तु

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई जात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
8. विचाराधीन उत्पाद का दायर पूर्ववर्ती अंतिम जाँच परिणाम के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए के समान ही रखा गया है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातित की जा रही वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ङ. घरेलू उद्योग

9. यह याचिका संयुक्त रूप से मै. सेंट-गोब्रैन इंडिया प्रा. लि., मै. सिसकम फ्लैट ग्लास इंडिया लि. और मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि. द्वारा दायर की गई है।
10. उपलब्ध सूचना के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। इसे अलावा याचिकाकर्ताओं का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का ‘प्रमुख हिस्सा’ बनता है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

च. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

11. यतः प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि इस बात की समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और इस बात की जाँच करेंगे कि क्या ऐसे शुल्क को हटाए जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

छ. जांच अवधि

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) जनवरी, 2018 - दिसम्बर 2018 तक की है। क्षति जांच अवधि में 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 -2018 की अवधि और जाँच अवधि शामिल हैं। तथापि, पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए पीओआई से बाहर के आकड़ों की भी जाँच की जा सकती है।

ज. प्रक्रिया

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में अधिसूचना सं. 14/25/2012-डीजीएडी दिनांक 10 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।
14. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,****संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

अ. समय-सीमा

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की सूचना देने वाले पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण (सीवी) की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण (एनसीवी) की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ड. असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi , the 1st May, 2019

(CASE No.:SSR-01/2019)

Subject: Initiation of Sunset review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE.

F. No. 7/3/2019-DGTR.—M/s Saint-Gobain India Pvt . Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd. and M/s. Gold Plus Glass Industry Limited (hereinafter referred to as the applicants or petitioners) have filed a joint application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Clear Float glass” (hereinafter also

referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. Whereas, the petitioners have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. BACKGROUND

3. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates was initiated by the Authority vide Initiation Notification No. 14/25/2012 DGAD dated 11th April, 2013. The Authority, vide its final findings No.14/25/2012-DGAD dated 10th October, 2014, recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No.48/2014-Customs (ADD) dated 11.12.2014.

B. SUBJECT COUNTRIES

4. The subject countries in the present sunset review investigation are Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the “subject goods”). The present investigation being a Sunset review, the scope of product under consideration is the same as that in the original investigation.
6. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975. The Custom classification is indicative only and in no way it is no way binding upon the product scope.

D. LIKE ARTICLE

7. The petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
8. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as ‘like article’ to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY

9. The petition has been filed by M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., M/s Sisecam Flat Glass India Ltd. and M/s Gold Plus Glass Industry Limited jointly.
10. As per the available information, the petitioners have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India. Further, the petitioners account for a major proportion in Indian production of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the petitioners as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

F. INITIATION OF SUNSET REVIEW

11. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

G. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation for the purpose of the present investigations is January 2018- December 2018. The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

H. PROCEDURE

13. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/25/2012-DGAD dated 10th October, 2014.
14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules *supra* shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

15. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
Parliament Street, New Delhi -110001.**

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

J. TIME LIMIT

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-Dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as **Confidential** (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as **Non-Confidential** (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "**confidential**" or "**non-confidential**" at the top of each page.

19. Information supplied **without any confidential marking** shall be treated as **Non confidential** and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version (CV) and two (2) copies of the non-confidential version (NCV) must be submitted by all the interested parties.
20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

24. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, 1995 any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

M. NON-COOPERATION

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General